IJIRSET
International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 11, Issue 10, October 2022

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 8.118

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 10, October 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1110052 |

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धियों का मूल्यांकन (मरुधरा ग्रामीण बैंक के विशेष संदर्भ में)

[1]Lal Chand Chahar & [2]Dr. (C.A) Yogesh Swami

[1]Assistant Professor, Dept. of EAFM, Govt. Lohia College, Churu, Rajasthan, India

[2]Faculty of Commerce and Management, Tantia University, Sri Ganganagar, Rajasthan, India

सार

ग्रामीण बैंक मोहम्मद युनुस द्वारा स्थापित था। इन्हें २००० में भारत सरकार द्वारा गाँधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

ग्रामीण बैंक (बांग्ला: *গ্রামীণ ব্যাংক*) बांग्लादेश में स्थापित एक माइक्रोफाइनेंस (छोटे ऋण) संगठन और सामुदायिक विकास बैंक है। यह गरीब लोगों को छोटे छोटे ऋण देता है बिना किसी समान के गिरवी रखे बिना। (जिसे माइक्रोक्रेडिट या "ग्रामीणक्रेडिट" के रूप में जाना जाता है)

ग्रामीण बैंक की स्थापना 1976 में [[चटगाँव विश्वविद्यालय]] के प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के कार्यकाल में हुई, इन्होने ग्रामीण गरीबों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए "ऋण प्रदान प्रणाली" को कैसे डिजाइन किया जाए, इसका अध्ययन करने के लिए एक शोध परियोजना के अंतर्गत शुरू की। ग्रामीण बैंक को अक्टूबर 1983 में स्वतंत्र बैंक के रूप में संचालित करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून द्वारा अधिकृत किया गया था।

2003 और 2007 के बीच इस बैंक ने काफी वृद्धि की। जनवरी 2011 तक, इस बैंक की उधर लेने वालों की कुल संख्या 84 लाख थी, और उनमें से 97% महिलाएं थी। 1998 में बैंक के "लो-कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम"(कम कीमतों पर घर का कार्यक्रम) ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता। 2006 में, इस बैंक और इसके संस्थापक, मुहम्मद यूनुस को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

हाल ही में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) में विभिन्न सुधारों पर चर्चा के लिये वित्त मंत्री और बैंक प्रमुखों के बीच बैठक हुई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की स्थापना 26 सितंबर, 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1975 में की गई थी।RRB वित्तीय संस्थान हैं जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं।RRB ग्रामीण समस्याओं से परिचित होने के साथ सहकारी विशेषताओं और वाणिज्यिक बैंक की व्यावसायिक एवं वित्तीय संसाधनों को जुटाने की क्षमता का विस्तार करतें हैं।वर्ष 1990 के दशक में सुधारों के बाद सरकार ने वर्ष 2005-06 में समेकन कार्यक्रम शुरू किया जिसके परिणामस्वरूप RRB की संख्या वर्ष 2005 में 196 से घटकर वित्त वर्ष 2021 में 43 हो गई और इन 43 RRBs में से 30 ने शुद्ध लाभ प्रदान किये। बैंक के बुनियादी कार्यों को संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है:

- ग्राहकों की बचत को सुरक्षा प्रदान करने के लिये,
- ऋण और पैसे की आपूर्ति बढ़ाने के लिये,
- वित्तीय प्रणाली में जनता के विश्वास को प्रोत्साहित करने के लिये,
- जनता की बचत जुटाने के लिये,
- अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिये ताकि समाज के हर वर्ग तक पहुँच सके,
- सभी ग्राहकों को उनकी आय के स्तर की परवाह किये बिना वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिये,
- समाज के हर तबके को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके सामाजिक समानता लाना।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 10, October 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1110052 |

परिचय

1974 के बांग्लादेश अकाल के दौरान मुहम्मद यूनुस ने 42 परिवारों के एक समूह को 27 डॉलर का एक छोटा ऋण दिया जिससे वे अपना खुद का समान बनाकर बेच सके ताकि वे साहूकार के ऋण के तहत उच्च ब्याज के बोझ के बिना, अपना जीवन यापन कर सके। यूनुस ऐसा समझते थे कि एक बड़ी आबादी को ऐसे ऋण उपलब्ध कराने से व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और बांग्लादेश में व्यापक ग्रामीण गरीबी को रोजगार उपलब्ध होगा।

मुहम्मद यूनुस ने अपने शोध और अनुभवो से ग्रामीण बैंक के सिद्धांतों को विकसित किया। ग्रामीण बैंक का बंगाली में अर्थ है गांव का बैंक। उन्होंने बांग्लादेश के चटगांव विश्वविद्यालय के रूरल इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट (ग्रामीण अर्थशास्त्र परियोजना) के साथ मिलकर एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में माइक्रोक्रिडिट (ऋण प्रदान प्रणाली) का विस्तार करना शुरू किया, ताकि ग्रामीण गरीबों को ऋण और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए उनकी विधि का परीक्षण किया जा सके। 1976 में, चटगाँव विश्वविद्यालय के आस पास जोबरा गाँव और अन्य गाँव को ग्रामीण बैंक की सेवा पाने के योग्य पहले क्षेत्र बन गए। इस बैंक परियोजना प्रयोग में सफल साबित होने के बाद, बांग्लादेश बैंक के समर्थन के साथ, 1979 में टंगैल जिले (राजधानी, ढाका के उत्तर में) तक बढ़ा दी गई थी। इस तरह बैंक की सफलता जारी रही और इसकी सेवाओं को बांग्लादेश के अन्य जिलों तक पहुंचाया गया।

2 अक्टूबर 1983 को बांग्लादेश सरकार के अध्यादेश के द्वारा, इस परियोजना को अधिकृत किया गया था और एक स्वतंत्र बैंक के रूप में इसे स्थापित किया गया था। शिकागो के एक सामुदायिक विकास बैंक शोरबैंक के बैंकर्स रॉन ग्रेज़ीविंस्की और मैरी हॉटन ने फोर्ड फाउंडेशन के अनुदान के तहत यूनुस को बैंक के आधिकारिक निगमन के साथ मदद की। बांग्लादेश में आए 1998 की बाढ़ के बाद बैंक की पुनर्भुगतान दर आर्थिक व्यवधान से ग्रस्त थी, लेकिन बाद के वर्षों में यह फिर ठीक हो गई। 2005 की शुरुआत तक, बैंक ने 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2008 के अंत तक, 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर गरीबों को दिया

2011 में, बांग्लादेश सरकार ने यूनुस को ग्रामीण बैंक से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, यह कहते हुए कि 72 साल की उम्र में, वह इस पद के लिए कानूनी सीमा से परे था।

2017 तक, बैंक की लगभग 2,600 शाखाएँ और 90 लाख उधारकर्ता थे, जिनकी पुनर्भुगतान दर 99.6% थी। कर्ज लेने वाली 97% महिलाएं थीं। बैंक बांग्लादेश के 97% गांवों में सक्रिय है। इसकी सफलता ने दुनिया भर के 64 से अधिक देशों में इसी तरह की परियोजनाओं को प्रेरित किया है, जिसमें ग्रामीण प्रकार की योजनाओं को वित्त करने के लिए विश्व बैंक की पहल भी शामिल है।

ग्रामीण बैंक अब अमीर देशों में भी विस्तार कर रहा है। 2017 के रूप में, ग्रामीण अमेरिका की ग्यारह अमेरिकी शहरों में इसकी 19 शाखाएँ थीं। इसके लगभग 100,000 उधारकर्ता जो की सभी महिलाएं थीं।

राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक , भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित, जिसका प्रधान कार्यालय जोधपुर में है, का गठन 01/04/2014 से किया गया था।
बैंक का संचालन क्षेत्र राज्य के जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर, जयपुर, नागौर, दौसा, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिलों में है।

RRBs से संबंधित चुनौतियाँ:

- बढ़ती लागत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के संचालन की बढ़ती लागत।
  - सरकार चाहती है कि वे अपनी कमाई बढ़ाने की दिशा में काम करें।
- सीमित गतिविधियाँ: कई शाखाओं के पास पर्याप्त व्यवसाय नहीं है, जिसके कारण उन्हें घाटा हो रहा है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में वे मुख्य रूप से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी सरकारी योजनाओं की पेशकश करते हैं।
- सीमित इंटरनेट बैंकिंग: वर्तमान में केवल 19 RRBs के पास इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएँ हैं और 37 के पास मोबाइल बैंकिंग लाइसेंस हैं।
  - मौजूदा नियम केवल उन्हीं RRBs को इंटरनेट बैंकिंग की पेशकश करने की अनुमति देते हैं जो न्यूनतम वैधानिक पूंजी जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (CRAR) 10% से अधिक बनाए रखते हैं।

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 10, October 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1110052 |

सरकार के सुझाव:

- सरकार ने RRBs को अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को ऋण देने के माध्यम से अपने साख आधार का विस्तार करने सहित डिजिटलीकरण की ओर बढ़ने के लिये कहा है ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।
- सरकार ने प्रायोजक बैंकों से RRBs को और मज़बूत करने, महामारी के बाद आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिये समयबद्ध तरीके से एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने का आग्रह किया।
  - साथ ही RRB पर एक कार्यशाला आयोजित करने और परस्पर सर्वोत्तम उपायों को साझा करने का सुझाव दिया।

सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किये गए सुधार:

- वर्षों से भारत की वित्तीय प्रणाली में लोगों के योगदान को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं।
  - वर्ष 1969 में भारत में मौजूद कई बैंकों के राष्ट्रीयकरण के रूप में बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ा सुधार हुआ इसी क्रम में वर्ष 1981 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई थी।
    - नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्थायी और निष्पक्ष कृषि को बढ़ावा देना और प्रभावी ऋण सहायता, संबंधित सेवाओं, संस्था विकास और अन्य नवीन पहलों के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना था।
- इसलिये नाबार्ड, RRBs को पुनर्जीवित करने की पहल का नेतृत्व करेगा।
  - इसके अलावा, विकास बैंक पहले से ही 22 RRBs के लिये एक रोडमैप पर काम कर रहा है, जिसके इस वर्ष के अंत तक लागू होने की उम्मीद है।
  - इस योजना में RRBs की शाखाओं द्वारा व्यवसाय के एक निश्चित स्तर तक पहुँच जाने पर इन्हें प्रायोजक बैंकों के साथ विलय करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।
  - पिछले वर्ष भारत सरकार ने क्षेत्रीय ऋणदाताओं को सशक्त करने हेतु सलाह देने के लिये नाबार्ड और RBI के सदस्यों के साथ एक पैनल का गठन किया था।
    - सरकार ने वित्तीय-वर्ष 2021-22 में RRBs के पुनर्पूंजीकरण के लिये 4,084 करोड़ रुपये का योगदान दिया है, जिसमें से 21 उधारदाताओं को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिये 3,197 करोड़ रुपये जारी किये गए।

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (Rajasthan Marudhara Gramin Bank- RMGB) की स्थापना **01 अप्रैल 2014** को हुई थी. यह राजस्थान स्थित दो ग्रामीण बैंको (Gramin Banks) में से एक है. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (Rajasthan Marudhara Gramin Bank- RMGB) 01 अप्रैल 2014 को राजस्थान स्थित तत्कालीन दो ग्रामीण बैंको, "**मरुधरा ग्रामीण बैंक** (Marudhara Gramin Bank)" और "**मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक** (Mewar Aanchalik Gramin Bank)" को मिलाकर बना था. इन दोनों पूर्ववर्ती ग्रामीण बैंको (Gramin Banks) के प्रायोजक बैंक क्रमशः "State Bank of Bikaner and Jaipr" और "ICICI Bank Ltd" थे. वर्तमान राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (Rajasthan Marudhara Gramin Bank- RMGB) का प्रायोजक बैंक **स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया** (State Bank Of India- SBI) है वर्तमान राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (Rajasthan Marudhara Gramin Bank- RMGB) का **हेड ऑफिस** (Head office) **जोधपुर**, **राजस्थान** में है. और यह राजस्थान के **15 जिलों** में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है.

01 अप्रैल 2014 को राजस्थान स्थित पूर्ववर्ती दोनों ग्रामीण बैंको के समामेलन (Amalgamation) के बाद बना राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (Rajasthan Marudhara Gramin Bank- RMGB), **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976** (RRB Act **1976)** के तहत काम कर रहा है. समामेलन (Amalgamation) के बाद बना राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (Rajasthan Marudhara Gramin Bank- RMGB) राजस्थान में स्थित दो ग्रामीण बैंको (Gramin Banks) में से एक है.

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 10, October 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1110052 |

विचार-विमर्श

31.03.2021 को राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (Rajasthan Marudhara Gramin Bank- RMGB) के **कुल व्यवसाय (** Total Business) की बात करें तो यह वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 12.81% बढ़कर **रू**23,309 **करोड़** के स्तर तक पहुंच गया है. जिसमें **रू**14078 **करोड़ जमा (**Total Deposit) और **कुल अग्रिम (**Total Advance) **रू**9,229 **करोड़** है. Total Deposit में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 12.63% तथा Total Advance में पिछले वित्त की वर्ष की तुलना में 13.09% की वृद्धि हुई है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में बैंक ने **रू**44.91 **करोड़ का शानदार** लाभ अर्जित किया है. बैंक का कुल लाभ पिछले वित्त वर्ष के रू4.61 करोड़ से 974.18 **प्रतिशत ज्यादा** है. बैंक का **सकल एनपीए (**Gross NPA) पिछले वित्त वर्ष के 6 प्रतिशत से घटकर 5.23 **प्रतिशत** रह गया है. वहीं अगर बैंक के **शुद्ध एनपीए (**Net NPA) की बात करें तो यह पिछले वित्त वर्ष के 3.56 प्रतिशत से मात्र 2.53 **प्रतिशत** रह गया है.

इसकी **कुल ब्रांचों की संख्या** (Total Branches) “701” है. जिसमें 526 रूरल शाखाएं (Rural Branches), 138 अर्ध शहरी शाखाएं (Semi Urban Branches) एवं 23 शाखाएं शहरी क्षेत्रों (Urban Branches) क्षेत्रों में एवं 14 शाखाएं मेट्रो (Metro Branches) क्षेत्रों में स्थित हैं. **राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (**Rajasthan Marudhara Gramin Bank- RMGB) ब्रांच नेटवर्क (Branch Network) के मामले में **राजस्थान** की सबसे बड़ी ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank) है.

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (Rajasthan Marudhara Gramin Bank- RMGB) की शाखाएं राजस्थान के 15 **जिलों** में फैली हुई हैं.

आगे की राह:

- कोर बैंकिंग समाधान (CBS) की तर्ज़ पर RRBs के लिये एक सामान्य ढाँचे की आवश्यकता है, ताकि वे सभी अपने ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएँ प्रदान कर सकें और अपनी पहुँच और लाभप्रदता को बढ़ा सकें।
- इंटरनेट बैंकिंग जैसी अन्य सुविधाओं का भी समावेश करना चाहिये।
- इसके अलावा उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने और बैंकिंग के विभिन्न अन्य आयामों तक पहुँचने की ज़रूरत है, जैसे व्यापारियों को ऋण प्रदान करना, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) अपनी लाभप्रदता बढ़ा सकें।

मुख्य बिंदु:

- 25 मार्च, 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस योजना में केंद्र के हिस्से के रूप में 670 करोड़ के परिव्यय के लिये अपनी मंज़ूरी दी है।
- हालाँकि सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत केंद्र के हिस्से की राशि को तभी जारी किया जाएगा जब प्रायोजक बैंकों द्वारा अपने आनुपातिक हिस्से की राशि जारी की जाएगी।

योजना के लाभ:

- केंद्रीय सरकार की इस योजना से क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के 'पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात' (Capital-to-risk Weighted Assets Ratio- CRAR) में सुधार होगा।
- यह योजना उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक अतिरिक्त वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020-21) के लिये न्यूनतम विनियामक पूँजी (Minimum Regulatory Capital) प्रदान करेगी जो वर्तमान में न्यूनतम 'पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात' (9%) बनाए रखने में असमर्थ थे।
- इस योजना से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संस्थागत मज़बूती प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी।
- COVID-19 के कारण देशव्यापी बंदी (Lockdown) के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय तरलता सुनिश्चित करने के लिये ग्रामीण बैंकों का आर्थिक रूप से मज़बूत होना बहुत ही आवश्यक है।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 10, October 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1110052 |

बैंकों का पुनर्पूंजीकरण:

- बैंक पुनर्पूंजीकरण से आशय, बैंकों के लिये अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराना है, जिससे बैंक के सफल संचालन के लिये आवश्यक पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूरा किया जा सके।
- भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ी शेयरधारक है, अतः संकट की स्थिति में इन बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की ज़िम्मेदारी भी सरकार की ही होती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण:

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 में शुरू किया गया था।
- वित्तीय वर्ष 2010-11 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण 'के.सी. चक्रवर्ती समिति' के सुझावों के आधार पर किया गया।
- के.सी. चक्रवर्ती समिति ने 21 राज्यों के 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना के तहत 2,200 करोड़ रुपए जारी करने का सुझाव दिया था।

पुनर्पूंजीकरण के लिये बजटीय आवंटन:

- वित्तीय वर्ष 2010-11 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिये केंद्र सरकार ने 1,100 करोड़ रुपए जारी किये थे।
- इसे बाद में वित्तीय वर्ष 2012-13, 2015-16 और पुनः वर्ष 2017 में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये बढ़ा दिया गया था।
- के.सी. चक्रवर्ती समिति के सुझावों के अनुरूप आज तक केंद्र सरकार द्वारा 1,395.64 करोड़ रुपए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिये जारी किये जा चुके हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 'नरसिंहम समिति (1975)' की सिफारिसों के आधार पर 26 सितंबर, 1975 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के तहत वर्ष 1975 में की गई थी।
- 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976' के माध्यम से इस अध्यादेश को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई थी।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादन गतिविधियों को आर्थिक तंत्र से जोड़कर उनका विकास करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, कलाकारों और छोटे उद्यमियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहयोग प्रदान करना था।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संचालन भारत सरकार, राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों के सहयोग से किया जाता है।
- इन बैंकों में भारत सरकार, प्रायोजक बैंकों और संबंधित राज्यों की हिस्सेदारी क्रमशः 50%, 35% और 15% होती है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विनियमन 'राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक' (National Bank for Agriculture and Rural Development-NABARD) के द्वारा किया जाता है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मज़बूती प्रदान करने और इनके पूंजी आधार को बढ़ने के लिये वर्ष 2011 के बाद सरकार ने तीन चरणों में इन बैंकों के समेकन (Consolidation) की शुरुआत की, जिससे देश में कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 (वर्ष 2005) से घटकर मात्र 45 रह गई है।

आज भी भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। इनमें से अधिकांश लोग कृषि, लघु और कुटीर उद्योग या ग्रामीण आवश्यकताओं से जुड़े छोटे व्यवसायों से जुड़े हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्र की ज़रूरतों के अनुरूप ऋण एवं अन्य बैंकिग सेवाएँ उपलब्ध करा कर तथा सरकार की योजनाओं के माध्यम से इस आबादी को देश के आर्थिक तंत्र से जोड़ने का काम करते हैं। सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की घोषणा से हाल के वर्षों में देश के विभिन्न

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 10, October 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1110052 |

व्यावसायिक क्षेत्रों में फैले आर्थिक दबाव और COVID-19 से उत्पन्न अनिश्चितता के बीच ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक चुनौतियों को दूर करने में सहायता प्राप्त होगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना 1975 में 26 सितंबर, 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादक गतिविधियाँ के विकास हेतु ऋण और अन्य सुविधाएँ प्रदान करने, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को, और उससे जुड़े और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए की गई थी।

परिणाम

01 अप्रैल 2014 के Amalgamation के बाद स्थापित हुए **राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक** (Rajasthan Marudhara Gramin Bank- RMGB) के Area Of Operation की बात की जाए, तो दोस्तों आपको बता दें राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (Rajasthan Marudhara Gramin Bank- RMGB) की शाखाएं राजस्थान के 15 **जिलों** में फैली हुई हैं. इन जिलों के नाम हैं, जालौर (Jalore), पाली (Pali), सिरोही (Sirohi), जोधपुर (Jodhpur), जयपुर (Jaipur), नागौर (Nagaur), दौसा (Dausa), जैसलमेर (Jaisalmer), बारमेड़ (Barmer), बीकानेर (Bikaner), श्रीगंगानगर (Sriganganagar), हनुमानगढ़ (Hanumangarh), उदयपुर (Udaipur), राजसमंद (Rajsamand) and प्रतापगढ़ (Pratapgarh).

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (Rajasthan Marudhara Gramin Bank- RMGB) में **टोटल एम्प्लाइज** (Total Employees) की संख्या की बात करें तो 31.03.2020 को बैंक में **कुल** 2607 **कर्मचारी** (Total Employees -2607) काम कर रहें हैं. जिसमें **अधिकारियों** (Officers) **की संख्या** 1442, **कार्यालय सहायक** (Office Assistant) **और कार्यालय परिचालक** (Office Attendant) **की कुल संख्या** 1165 **है** है. जो राजस्थान के 15 जिलों में फैली 701 शाखाओं पर अपनी सेवाएं दे रहें हैं.

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (Rajasthan Marudhara Gramin Bank- RMGB) के **चेयरमैन** (Chairman) की बात करें तो वर्तमान (16-10 -2021) में को बैंक के चेयरमैन Mr. Satyendra Kumar Jain (**ज्ञानेंद्र कुमार जैन**) हैं. बैंक में 5 **महाप्रबधंक** (General Manager) **श्री राम डेरवाल** (Shri Ram Derwal), **अनिल सोगानी** (Anil Sogani), **आर. के. गुप्ता** (R.K. Gupta), **के. एन. द्विवेदी** (K. N. Dwevedi) **और संजीव कुमार** (Sanjeev Kumar) हैं. यह सभी अधिकारी स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (State Bank Of India- SBI) के अधिकारी हैं. और यह राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (Rajasthan Marudhara Gramin Bank- RMGB) में डेपुटेशन पर हैं.

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (Rajasthan Marudhara Gramin Bank- RMGB) के प्रायोजक बैंक (Sponsors Bank) की बात करें, तो राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (Rajasthan Marudhara Gramin Bank- RMGB) का **प्रायोजक बैंक** (Sponsors Bank), State Bank Of India (SBI) है.

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (Rajasthan Marudhara Gramin Bank- RMGB) के तीन Owner हैं. जिनके 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार (Central Government) की, 35 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रायोजक बैंक (Sponsors Bank) की और 15% हिस्सेदारी राज्य सरकार (State Government) की है. आपको बता दें देश की सभी ग्रामीण बैंको (RRBs) में Ownership का Ratio यही है.

निष्कर्ष

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक बैलेंस इंक्वायरी टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े। दोस्तों इस बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 2014 में मरुधरा ग्रामीण बैंक और मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक के विलय से हुई और इस बैंक का मुख्यालय राजस्थान के जोधपुर जिला में स्थित है।

इस बैंक की काफी सारी शाखाएं हैं और खेत क्षेत्र इस बैंक का मुख्य कार्य क्षेत्र है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा यह बैंक प्रायोजित है। उपयोगकर्ताओं के लिए खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई है। और विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे कि मिस्ड कॉल, सेवा एसएमएस सेवा, एटीएम सेवा आदि को भी उपलब्ध कराया गया है। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक बैलेंस चेक करने के लिए पढ़ते रहे।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 10, October 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1110052 |

मिस कॉल द्वारा राजस्थान मरुधरा बैंक बैलेंस चेक करें

आप मिस कॉल सेवा का उपयोग करके भी बैलेंस चेक कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से बैंक द्वारा प्रदान किए गए टोल फ्री नंबर 87501 87504 पर मिस्ड कॉल करना होगा। मिस्ड कॉल करने के बाद आपकी कॉल स्वचालित रूप से कट जाएगी और एसएमएस के माध्यम से शेष राशि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।

कस्टमर केयर नंबर द्वारा राजस्थान मरुधरा बैंक बैलेंस चेक करें

उपयोगकर्ताओं के लिए कस्टमर केयर सुविधा द्वारा बैलेंस के बारे में जानकारी हासिल करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके लिए आपको ग्राहक सेवा केंद्र नंबर 0291 259 3100 पर कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए अपना पंजीकृत नंबर का इस्तेमाल करें फिर निर्देशों का पालन करके बैलेंस खाते के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अन्य सहायता के विवरण को भी जान सकते हैं।

मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा राजस्थान मरुधरा बैंक बैलेंस चेक करें

आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी शेष राशि के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से बैंक द्वारा प्रदान किए गए फ्री एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद रजिस्टर करके आप लॉग इन करें। फिर उसके बाद अपने अकाउंट में जाकर शेष राशि के बारे में जानकारी पाएं। शेष राशि के बारे में जानकारी पानी के साथ अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। [Click Here]

नेट बैंकिंग द्वारा राजस्थान मरुधरा बैंक बैलेंस इंक्वायरी करें

इंटरनेट बैंकिंग द्वारा बैलेंस चेक करने की सुविधा काफी ज्यादा आसान है इसको कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और यह 24 घंटे उपलब्ध होती है इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। और आप मोबाइल या फिर लैपटॉप, पीसी पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

आपको राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और खुद का पंजीकरण करना होगा। यदि आप पहले से पंजीकृत है तब आपको केवल लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर वेबसाइट में लॉगिन है। उसके बाद अकाउंट में जाकर शेष राशि के बारे में जानकारी हासिल करनी है।

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक बैलेंस इंक्वायरी करने के अन्य विकल्प

आप किसी अन्य विकल्पों से बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं तब इसके लिए आपको एटीएम का सहारा लेना होगा। एटीएम में जाने के बाद आप डेबिट कार्ड स्वाइप करें। निर्देशों का पालन करके अब शेष राशि के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।

दूसरे विकल्पों में आप अपने निकटतम बैंक शाखा में जाकर अधिकारी से पासबुक अपडेट करवाने की मांग कर सकते हैं। जिसके बाद आपको शेष राशि के बारे में जानकारी मिलने के साथ-साथ ट्रांजिशन की जानकारी भी मिलेगी।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 10, October 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1110052 |

सेवा का लाभ लेने के लिए मरुधरा ग्रामीण बैंक में रजिस्ट्रेशन कैसे करें

जो उपयोगकर्ता इन सभी सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा। और अधिकारी से रजिस्ट्रेशन करने की मांग करनी होग।

जिसके बाद आपको एसएमएस के माध्यम से यह जानकारी मिल जाएगी। और आप इसके बाद सभी सेवाओं का लाभ जैसे कि मिस्ड कॉल सेवा, s.m.s. सेवा और कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर सेवा का लाभ उठाकर बैलेंस चेक कर सकते हैं।

संदर्भ

1. "Grameen Bank Act 2013". The Daily Star. मूल से 30 दिसंबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 December 2013.
2. ↑ "Short Biography of Mr. Abul Khair Md. Monirul Hoque (Acting Managing Director)". मूल से 3 अक्तूबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 दिसंबर 2019.
3. ↑ "Profit and Loss Account". Grameen Bank. मूल से 31 मार्च 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 September 2011.
4. ↑ "Balance Sheet (1983–2010) in BDT". Grameen Bank. मूल से 27 सितंबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 September 2011.
5. ↑ "Grameen Bank on Track to Log Its Highest Profit". Grameen Bank. मूल से 15 अगस्त 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 August 2018.
6. ↑ "The Nobel Peace Prize for 2006". The Nobel Peace Prize for 2006. 13 October 2006. मूल से 19 अक्तूबर 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 October 2006.
7. ↑ Anand Giridharas; Keith Bradsher (13 October 2006). "Microloan Pioneer and His Bank Win Nobel Peace Prize". New York Times. मूल से 24 अप्रैल 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 October 2006.
8. ↑ "History". Grameen Bank. मूल से 11 मार्च 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 December 2011.
9. ↑ Rahman, Aminur (2001). Women and Microcredit in Rural Bangladesh: Anthropological Study of Grameen Bank Lending. Boulder, Colorado: Westview Press. पृ° 4. आई°ऍस°बी°ऍन° 978-0-8133-3930-6.
10. ↑ Brandon Glenn (16 October 2006). "ShoreBank leaders had hand in Nobel prize". Chicago Business News. अभिगमन तिथि 15 May 2007.
11. ↑ Papa, Michael J.; Arvind Singhal; Wendy H. Papa (2006). Organizing for Social Change: A Dialectic Journey of Theory and Praxis. Sage Publications. पृ° 72. आई°ऍस°बी°ऍन° 978-0-7619-3435-6.
12. ↑ Grameen Bank Historical Data Archived 2013-08-23 at the Wayback Machine. Retrieved 22 June 2009.
13. ↑ Polgreen, Lydia; Bajaj (2 March 2011). "Microcredit Pioneer Ousted, Head of Bangladeshi Bank Says". The New York Times. मूल से 19 अक्तूबर 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 October 2012.
14. ↑ Cosic, Miriam (2017-03-29). "'We are all entrepreneurs': Muhammad Yunus on changing the world, one microloan at a time". Guardian. मूल से 9 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 August 2017.
15. ↑ "About us". Grameem Bank. मूल से 2 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 August 2017.
16. ↑ Khandker, Shahidur R.; Baqui, M. A.; Khan Z. H. (1995). Grameen Bank: Performance and Sustainability. World Bank Publications. पृ° vi. आई°ऍस°बी°ऍन° 978-0-8213-3463-8.

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor: 8.118

doi crossref

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com

Scan to save the contact details

www.ijirset.com